

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 20 फरवरी, 2025

विषय: पीएम- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 318/17/2024, दिनांक 23.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में आरम्भ की गयी पीएम- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर क्षमता में वृद्धि करना है, ताकि आवासीय परिवारों को स्व विद्युत उत्पादन हेतु सशक्तिकरण किया जा सके।

2- कुल रू0 75,021 करोड़ की लागत के साथ उक्त योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 01 करोड़ परिवारों तक योजना का क्रियान्वयन करना है। उक्त योजनान्तर्गत रूफटॉप सोलर स्थापित किये जाने में उपभोक्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन के रूप में रू0 1,000 करोड़ के परिव्यय का संघटन किया गया है। उक्त संघटक के रूप में शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में योजना के उन्नयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को रू0 1,000/- प्रति स्थापना पर प्रत्यक्ष सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- उक्त योजना के उन्नयन हेतु जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों, यथा- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत) स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन तथा आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से सक्रिय सहभागिता की जायेगी।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीएम- सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत जागरूकता प्रसार हेतु डोर-टू-डोर मोबिलाइजेशन कैम्पेन, सूचना, शिक्षा एवं संचार जैसी गतिविधियों का आयोजन किये जाने, योजना के लाभों के सम्बन्ध में जागरूकता प्रसार एवं उपभोक्ताओं की प्रतिभागिता हेतु शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं, वेन्डरों, बैंकों एवं डिस्कॉम् के सहयोग से स्थानीय मेलों के आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें, ताकि पीएम- सूर्य घर बिजली मुफ्त

बिजली योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने में योगदान दिया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

Signed by

Nitesh Kumar Jha

Date: 18-02-2025 13:56:22

(नितेश कुमार झा),

सचिव।

संख्या- 276979, /IV(2)-श0वि0-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 23.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन
3. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त नगरपालिका/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Gaurav Kumar

Date: 19-02-2025 14:03:11

(गौरव कुमार),

अपर सचिव।





सत्यमेव जयते

सुदीप जैन, भा.प्र.से.  
SUDEEP JAIN, IAS



अपर सचिव  
भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
ADDITIONAL SECRETARY  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

D.O. No. 318/17/2024-Grid Connected Rooftop-Part(6)

Dated: 23-01-2025

Dear Shri Nitish Kumar Iha,

As you are aware, the Government of India has launched the PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana in February 2024. This flagship initiative aims to increase the share of rooftop solar (RTS) capacity while empowering residential households to generate their own electricity. With a total outlay of ₹75,021 crore, the scheme targets one crore households and will be implemented until FY 2026-27. As on 22.01.2025, a total of 42.97 lakh applications have been received from residential consumers via the National Portal of the scheme and approximately 8.3 lakh households have benefited from the scheme by installation of RTS.

2. To encourage the participation of consumers under the scheme for installation of RTS, MNRE has introduced a component to incentivize local bodies with an outlay of ₹1,000 crore. Under this component, an incentive of **₹1,000 per installation** will be provided to ULBs/PRIs in the form of direct support for promoting the scheme within the respective jurisdiction of ULBs/PRIs.

3. Active participation of the District Authorities, Urban Local Bodies (ULBs) such as Municipal Corporations, Municipal Councils, Nagar Panchayats, and other entities recognized by the Ministry of Housing and Urban Affairs, along with Panchayati Raj Institutions (PRIs) including Gram Panchayats, is important to promote the scheme by organizing events and outreach programs. These may include Door-to-door mobilization campaigns, Information, Education & Communication (IEC) activities to spread awareness, organizing local melas to bring together local bodies (ULBs/PRIs), vendors, banks, and DISCOMs to catalyze consumer participation and raise awareness about the scheme's benefits.

4. Your proactive involvement and support are crucial for the success of this flagship initiative. Together, we can ensure that the PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana achieves its objectives and significantly contributes to India's renewable energy goals.

संख्या 25.14/नोसो-सो/20

दिनांक: देहरादून 06/02/25

To:

Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Urban Affairs) of Uttarakhand

CC:

श्रीव कुमार  
अपर सचिव  
राष्ट्रीय विकास/सूचना प्रौद्योगिकी  
सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग  
उत्तराखण्ड सरकार

Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, with a request to advise/direct the Urban Development Departments of States and Union Territories to promote the scheme.  
Secretary, Panchayati Raj Institutions (PRIs), with a request to advise/direct the Panchayati Raj Departments of States and Union Territories to promote the scheme.

Yours sincerely,

(Sudeep Jain)

